

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर 2017—अग्रहायण 9, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. 28573-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 30 नवम्बर 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१७

## दण्ड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) विधेयक, २०१७

## विषय सूची

खण्ड :

## अध्याय—एक

१. संक्षिप्त नाम.

## अध्याय—दो

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का संख्यांक ४५ का संशोधन.

३. धारा ३५४ क का लोप.

४. धारा ३५४ ख का संशोधन.

५. धारा ३५४ घ का संशोधन.

६. धारा ३७६कक का अंतःस्थापन.

७. धारा ३७६घक का अंतःस्थापन.

८. धारा ४९३ क का अंतःस्थापन.

## अध्याय—तीन

९. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, क्रमांक १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.

१०. धारा २९ का संशोधन.

११. धारा ११० का संशोधन.

१२. धारा १९८ का संशोधन.

१३. धारा ४३७ का संशोधन.

१४. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१७

## दण्ड विधि ( मध्यप्रदेश संशोधन ) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय—एक

## प्रारंभिक

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम.

## अध्याय—दो

## भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय दण्ड संहिता, (१८६० का ४५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५ का संशोधन.

३. भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००४ (क्रमांक १४ सन् २००४) द्वारा यथा अंतः स्थापित मूल अधिनियम की धारा ३५४क का लोप किया जाए.

धारा ३५४क का लोप.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५४ख में, शब्द “वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा”, के स्थान पर शब्द “वह प्रथम बार दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा” स्थापित किए जाएं.

धारा ३५४ख का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३५४घ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ३५४घ का संशोधन.

“(२) जो कोई भी पीछा करने का अपराध कारित करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में पर्याप्त तथा विशेष कारणों को उल्लिखित करते हुए, विनिर्दिष्ट न्यूनतम कारावास से कम कालावधि के कारावास का कोई दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा.”.

धारा ३७६कक का  
अंतःस्थापन.

बारह वर्ष आयु तक  
की स्त्री के साथ  
बलात्संग के लिए  
दण्ड.

६. मूल अधिनियम की धारा ३७६क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३७६कक. जो कोई, बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग करता है तो वह मृत्युदण्ड से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.”.

धारा ३७६घक का  
अंतःस्थापन.

बारह वर्ष तक की  
आयु की स्त्री के  
साथ सामूहिक  
बलात्संग के लिए  
दण्ड.

७. मूल अधिनियम की धारा ३७६घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३७६घक. जहां बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री के साथ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह मृत्युदण्ड से अथवा कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.”.

धारा ४९३क का  
अंतःस्थापन.

विधिपूर्ण विवाह का  
प्रवचनपूर्वक  
विश्वास दिलाते हुए  
किसी व्यक्ति द्वारा  
कारित सहवास  
अथवा मैथुन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४९३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“४९३क. प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रवचन द्वारा किसी स्त्री को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे विवाह करेगा और इस प्रकार उस स्त्री के साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.”.

### अध्याय—तीन

### दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को  
लागू हुए रूप में  
केन्द्रीय अधिनियम,  
क्रमांक १९७४ का  
संख्यांक २ का  
संशोधन.

९. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २९ का  
संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(एक) उपधारा (२) में, शब्द “दस हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “एक लाख रुपए” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द “पांच हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पच्चीस हजार रुपए” स्थापित किए जाएं.

धारा ११० का  
संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ११० में, खण्ड (घ) में, शब्द, अंक और कोष्ठक “भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) के अध्याय बारह के अधीन” के स्थान पर, “शब्द, अंक और कोष्ठक” भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) के अध्याय बारह के अधीन या इस संहिता की धारा ३५४, धारा ३५४क, धारा ३५४ख, धारा ३५४घ या धारा ५०९ के अधीन” स्थापित किए जाएं.

१२. मूल अधिनियम की धारा १९८ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :— धारा १९८ का संशोधन.

“परन्तु यह और कि भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा ४९३ या धारा ४९३क के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी लिया जा सकेगा.”.

१३. मूल अधिनियम की धारा ४३७ में, उपधारा (१) में, चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :— धारा ४३७ का संशोधन.

“परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति, यदि उसके द्वारा स्त्री के विरुद्ध अपराध कारित किया जाना अभिकथित किया गया है, जो कम से कम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है, इस धारा के अधीन लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा.”.

१४. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक “१-भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध के अधीन”,— प्रथम अनुसूची का संशोधन.

(एक) दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००४ (क्रमांक १५ सन् २००४) द्वारा यथा अंतःस्थापित धारा ३५४क से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(दो) धारा ३५४ख तथा धारा ३५४घ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय अथवा असंज्ञेय	जमानतीय अथवा अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“३५४ख.	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग.	प्रथम दोषसिद्धि पर कम से कम ३ वर्ष का कारावास किन्तु जो ७ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
		द्वितीय या पश्चात्पूर्ती दोषसिद्धि पर कम से कम ७ वर्ष का कठोर कारावास किन्तु जो १० वर्ष तक का हो सकेगा और न्यूनतम १ लाख रुपए का जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
३५४घ.	पीछा करना	प्रथम दोषसिद्धि पर ३ वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट”
		द्वितीय या पश्चात्पूर्ती दोषसिद्धि पर कम से कम ३ वर्ष का कारावास किन्तु जो ७ वर्ष तक का हो सकेगा और न्यूनतम १ लाख रुपए जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट”;

(तीन) धारा ३७६क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“३७६कक.	१२ वर्ष तक की आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति.	मृत्युदंड, कम से कम १४ वर्ष का कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय”;

(चार) धारा ३७६घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“३७६घक. १२ वर्ष तक की आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग.	मृत्युदंड, कम से कम २० वर्ष का कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना.		संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय”;

(पांच) धारा ४९३ से संबंधित प्रविष्टियों में, कॉलम ४ में, शब्द “असंज्ञेय” के स्थान पर, शब्द “संज्ञेय” स्थापित किया जाए;

(छः) धारा ४९३ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“४९३क.	विधिपूर्ण विवाह का प्रवचनापूर्वक विश्वास दिलाते हुए किसी व्यक्ति द्वारा कारित सहवास अथवा मैथुन.	कारावास जो ३ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट”.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि स्त्रियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, हमले अथवा आपराधिक बल के प्रयोग के अपराध दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं. बलात्संग और सामूहिक बलात्संग के अपराध बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं. पिछले तीन वर्षों के दौरान छेड़छाड़ के पश्चात् स्त्रियों की आत्महत्या के बहुत से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. बारह वर्ष या उससे कम वर्ष की स्त्रियों का यौन शोषण और दुरुपयोग जघन्य अपराध है और इनसे प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है.

२. स्त्रियों के विरुद्ध अपराध के संभावित अपराधियों को डराकर रोकने और भारत के संविधान में यथाप्रतिष्ठापित स्त्री की पूर्ण स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान उपबंधों में दंड और जुर्माने को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतएव, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५)को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया है.

४. दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंधों के क्रियान्वयन में भी कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभूत की गई हैं. उपरोक्त को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना आवश्यक समझा गया है.

५. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(१) धारा २९ में विनिर्दिष्ट दंड की मात्रा में वृद्धि की गई है.

(२) धारा ४३७ में यह प्रस्तावित है कि भले ही स्त्री के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध ७ से अनिम्न वर्षों से दंडनीय है, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा.

(३) भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की कतिपय धाराओं को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, अतएव, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में परिणामिक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

६. अतएव, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया है.

७. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २७ नवम्बर, २०१७

रामपाल सिंह

भारसाधक सदस्य.